

दिनांक 8.6.2010 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कार्यकारी समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 8.6.2010 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया:-

1. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
2. प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग
3. प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग
4. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग
5. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
6. प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
7. प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग
8. शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग
9. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री
10. विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग
11. निदेशक, मौसम विभाग, जयपुर।

सर्वप्रथम शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा पश्चिमी राजस्थान, विशेषतः जैसलमेर, जोधपुर एवं बीकानेर जिलों में गत 2 दिनों में हुई मानसून पूर्व अतिवृष्टि से पशुधन एवं सम्पत्ति को हुए नुकसान का एक फौरी विवरण प्रस्तुत किया। यह भी जानकारी दी गई कि तत्सम्बन्धी विस्तृत सर्वे के लिये जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किये जा चुके हैं। जोधपुर जिले के फलौदी में पशु धन एवं लोगों के कच्चे-पक्के मकानों को हुये नुकसान की प्रारम्भिक जानकारी भी पेश की। उन्होंने अवगत कराया कि भारी वर्षा की जानकारी प्राप्त होते ही "राज्यस्तरीय नियन्त्रण कक्ष" (State EOC) को चालू कर दिया गया है, जो स्थिति सामान्य होने तक चालू रहेगा। उन्होंने बताया कि आगामी मानसून व सम्भावित बाढ़ की तैयारियों के सम्बन्ध में आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री महोदय की अध्यक्षता में सम्बन्धित विभागों की बैठक आयोजित की जा चुकी है। साथ ही बाढ़ सम्बन्धी खोज व बचाव कार्यों के लिये सभी जिलों को 3-3 लाख रुपये का बजट भी आवंटित किया जा चुका है।

प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन द्वारा बताया गया कि प्रभावित जिलों में पशुओं की उपचार व्यवस्था कर दी गई है व औषधियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। फलौदी, कोलायत आदि प्रभावित स्थानों में पशु चिकित्सकों के दल रवाना कर दिये गये हैं। उन्होंने क्षेत्र में मरे हुये पशुओं का निस्तारण शीघ्र ही और स्थानीय स्तर पर कराने पर जोर दिया। प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अतिवृष्टि से सड़कों एवं यातायात पर हुये प्रभाव की जानकारी दी व क्षतिग्रस्त सड़कों की शीघ्र मरम्मत करवाने हेतु उठाये जा रहे कदमों की जानकारी दी। मुख्य सचिव महोदय द्वारा जैसलमेर-जोधपुर सड़क को शीघ्र चालू कराने के निर्देश दिये।

प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सामान्य बनी हुई होने की जानकारी दी। साथ ही, क्षेत्र में जो पानी भराव की स्थिति उत्पन्न हुई है उसके निस्तारण के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही से अवगत कराया।

प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा, आपूर्ति की जा रही पेयजल की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिये उठाये जा रहे कदमों एवं सम्भावित बीमारियों की चिकित्सा के सम्बन्ध में विभाग की रणनीति से अवगत कराया। उन्होंने जिलों में डाक्टरों के बड़ी संख्या में पद खाली होने की जानकारी देते हुये, इन्हें शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता प्रतिपादित की। शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता द्वारा अवगत कराया गया कि यूनीसेफ के प्रतिनिधि ने उन्हें आवश्यक दवाइयों व चिकित्सा उपलब्ध कराने में सहयोग करने का प्रस्ताव दिया है, जिस पर विभाग विचार कर आवश्यक निर्णय ले।

प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग ने शहरों में मानसून पूर्व ही नालों की सफाई सुनिश्चित करने हेतु की गई कार्यवाही से अवगत कराया। शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता ने इस सम्बन्ध में द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिकाओं में राहत कार्यों के तहत नाला सफाई सम्बन्धी कार्य भी अनुमत किये हुये होने की जानकारी दी। मुख्य सचिव महोदय द्वारा जानकारी चाहने पर प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा, आवश्यकता पड़ने पर भोजन पैकेट एवं अन्य रसद सामग्री उपलब्ध कराने की पूरी तैयारी विभाग द्वारा किये हुये होने की जानकारी दी।

निदेशक, मौसम विभाग ने बताया कि जो कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ था वह पूर्वी राजस्थान की ओर बढ़ गया है तथा काफी कमजोर भी पड़ गया है और अगले 24 घंटे में मौसम पूर्णतः सामान्य होने की संभावना से अवगत कराया।

प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग ने बताया कि स्थिति के मध्येनजर पुलिस पूरी तरह सतर्क है। आरएसी की एक कम्पनी पहले से ही तैनात है। जहां भी आवश्यकता होगी टीम खाना कर दी जायेगी।

जहां तक जैसलमेर जिले के लाठी गांव में सेना आने का प्रश्न है, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता ने बताया कि सेना को औपचारिक रूप से बुलाया नहीं गया था, अपितु चूंकि सेना की एक टुकड़ी निकट ही उपलब्ध थी। अतः सम्बन्धित एस.डी.ओ. द्वारा अपने स्तर पर सेना से मदद का निवेदन किया था, जिसे मानते हुये सेना द्वारा मौके पर पहुंच कर मदद की गई और पानी से घिरे लोगों को सुरक्षित निकाला गया।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि जान-माल की जो भी क्षति हुई है उसका जल्द से जल्द सर्वे कराया जाये, आपदा राहत निधि के नोर्स के अनुसार जो भी राहत राशि देय बनती है उसका तुरन्त वितरण प्रारम्भ करवाया जाये तथा जल प्लावित क्षेत्रों में सड़कों को हुई क्षति के कारण यातायात को प्रभावित होने से रोकने के लिये शीघ्र मरम्मत सुनिश्चित की जाये।

शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता ने अवगत कराया कि बीकानेर के मनचेतिया बांध के टूटने की आशंका व्यक्त की गई थी। मौके पर रात भर निगरानी रखवाई गई थी जो अभी भी जारी है तथा बांध सुरक्षित है। प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि मलेरिया की रोकथाम के लिये की जाने वाली अग्रिम कार्यवाही पूर्व में ही प्रारम्भ हो चुकी है।

प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन ने बताया कि बड़ी संख्या में बनते जा रहे एनीकटों के कारण मुख्य बांध पूर्णतः खाली ही रह जाते हैं। अतः नरेगा विभाग में कोई भी एनीकट तभी बनाया जाना चाहिये जब जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर ली जाये। इस सम्बन्ध में नरेगा की ओर से आवश्यक निर्देश जारी किये जाने चाहिये। उनके सुझाव पर मुख्य सचिव महोदय द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में मरे हुये पशुओं का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने एवं शहरी क्षेत्रों में समय रहते नालों की सफाई का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये।

अन्त में बैठक सघन्यवाद समाप्त हुई।

शासन उप सचिव